RESPONSE TO QUERIES ON THE TENDER DOCUMENT FOR LEASING OF AIRFIELDS OF GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH DURING PRE-BID CONFERENCE HELD ON 03RD MAY 2017 AT M.P BHAWAN, NEW DELHI – 110 021

Tender reference number: Ref. No. F-42/1/LA/08 Dated: 04/04/2017

S. No	REFERENCE SECTION OF TENDER DOCUMENT	QUERY	RESPONSE
A	B	C	D
1.	2.9	Is construction of Hangars / Terminals permitted on the Airport / Airstrip land?	Yes
2.	2.9	Can modifications be made to the boundary wall to accommodate additional parking / hangar space on private land adjoining the airfield?	Yes, post permission of the Government.
3.	-	Is there a minimum reserve price for the bid?	No
4.	-	Will the government support financially in upgradation of airports for night landing and instrument landing, if required?	No
5.	-	In case the airport is to be approved for licenced category from DGCA, will the Govt of MP provide the necessary Security, fire and ambulance services?	NA
6.	2.21	Ref: 2.21.6 Page 29 Point (a) If a Bidder submits a non-responsive Bid; Subject however that in the event of encashment of Bid Security occurring due to operation of this para 2.22.7 (a), the damage so claimed by the Authority shall be restricted to 5% of the value of Bid Security. ------ However Point 2.22.7 does not exist in the Tender Document.	Please read 2.22.7(a) as 2.21.6(a).
7.	-	Incase the airstrip is included in the Regional Connectivity Scheme, what would happen to the lease and who would bear the cost of certifying the aerodrome?	NA

A	B	C	D
8.	2.	Please clarify the increment in the annual licence fee, as it appears differently at different pages.	Please refer to S No. 03 and 04 of Amendment dtd 06/05/2017 to the Tender Document no F-45/Jet lease/109 Dated: 3rd Feb 2017
9.	Appendix VII	Since some airfields are already occupied by some companies / flight schools / aero sport companies, and these airstrips may not be available for bidding to any other party in this bid, it is strongly recommended that these existing parties who have already leased airstrips may be barred from bidding in this tender as it would create a monopoly and make entry barriers for new entrants, alternatively all the airstrips may be open for bidding to all the parties.	Please refer to S No. 05 of Amendment dtd 06/05/2017 to the Tender Document no F-45/Jet lease/109 Dated: 3rd Feb 2017
10.	2.1.10	We were delighted to see the current interest of the authorities towards the development of Aviation industry in Madhya Pradesh by leasing the airstrip for aviation activity. But yesterday we came to know that there is a barrier for any society/firm/trust to be a part of the development of aviation in the state of Madhya Pradesh. There is no provision for any society/firm/trust to take part in bidding/putting up the tender for operation/development of any airstrip in Madhya Pradesh. I would like to draw your attention towards various societies, who are serving aviation industry since last few decades in M.P. and other parts of the country, selflessly. We believe and it is clearly evident that commercial companies are for-profit ventures and their mission differs in an important way from that of the societies, which address the full gamut of concerns and genuine need of the aviation sector. That is why a society is definitely one of the most important pillar in supporting the aviation sector in the state. By not allowing any society/firm/trust in the bidding/tender process, aviation industry will be at great loss by losing experienced and dedicated institutions, who have committed themselves in serving the nation and aviation industry at large. Hence, we request you to reconsider your decision of not letting any society/firm/trust in the bidding/tender process of leasing air strips and let us together contribute for the development of our nation and Aviation sector by taking part in this bidding process for lease of Airstrips in Madhya Pradesh.	Please refer to S No.01 and 02 of Amendment dtd 06/05/2017 to the Tender Document no F-45/Jet lease/109 Dated: 3rd Feb 2017

A	B	C	D
11.	Appendix VII	As discussed during the pre bid meeting, we request a clarification as to weather the government is going to remove the names of airfields where flying activity is already happening or where the govt. has already leased out the airport to some party earlier. We also note that airfields like Tekanpur, which are for the exclusive use of BSF are also mentioned in the list. We request you to kindly amend the list of airfields offered suitably to avoid confusion.	Please refer to S No. 05 of Amendment dtd 06/05/2017 to the Tender Document no F-45/Jet lease/109 Dated: 3rd Feb 2017
12.	Appendix VII	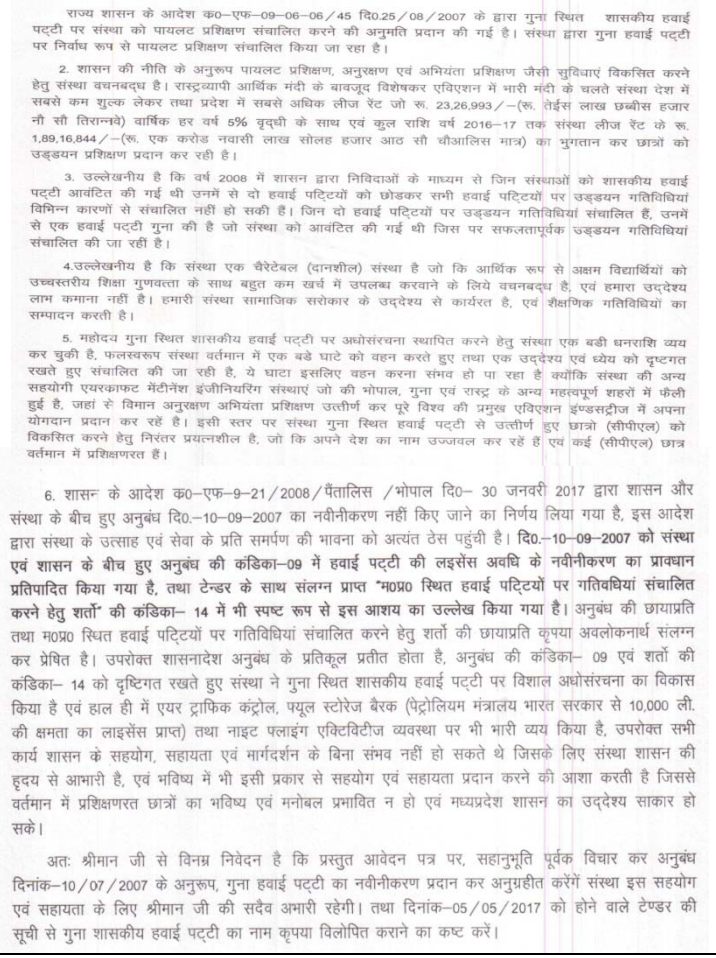 राज्य शासन के आदेश क0–एफ–09–06–06/45 दि0.25/08/2007 के द्वारा गुना स्थित शासकीय हवाई पट्टी पर संस्था को पायलट प्रशिक्षण संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। संस्था द्वारा गुना हवाई पट्टी पर निर्बाध रूप से पायलट प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है। 2. शासन की नीति के अनुरूप पायलट प्रशिक्षण, अनुरक्षण एवं अभियंता प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं विकसित करने हेतु संस्था वचनबद्ध है। राष्ट्रव्यापी आर्थिक मंदी के बावजूद विशेषकर एविएशन में भारी मंदी के चलते संस्था देश में सबसे कम शुल्क लेकर तथा प्रदेश में सबसे अधिक लीज रेंट जो रू. 23,26,993/–(रू. तेईस लाख छब्बीस हजार नौ सौ तिरान्वे) वार्षिक हर वर्ष 5% वृद्धी के साथ एवं कुल राशि वर्ष 2016–17 तक संस्था लीज रेंट के रू. 1,89,16,844/–(रू. एक करोड नवासी लाख सोलह हजार आठ सौ चौआलिस मात्र) का भुगतान कर छात्रों को उड्डयन प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। 3. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2008 में शासन द्वारा निविदाओं के माध्यम से जिन संस्थाओं को शासकीय हवाई पट्टी आवंटित की गई थी उनमें से दो हवाई पट्टियों को छोडकर सभी हवाई पट्टियों पर उड्डयन गतिविधियां विभिन्न कारणों से संचालित नहीं हो सकी हैं। जिन दो हवाई पट्टियों पर उड्डयन गतिविधियां संचालित हैं, उनमें से एक हवाई पट्टी गुना की है जो संस्था को आवंटित की गई थी जिस पर सफलतापूर्वक उड्डयन गतिविधियां संचालित की जा रही है। 4.उल्लेखनीय है कि संस्था एक चैरेटेबल (दानशील) संस्था है जो कि आर्थिक रूप से अक्षम विद्यार्थियों को उच्चस्तरीय शिक्षा गुणवत्ता के साथ बहुत कम खर्च में उपलब्ध करवाने के लिये वचनबद्ध है, एवं हमारा उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। हमारी संस्था सामाजिक सरोकार के उद्देश्य से कार्यरत है, एवं शैक्षणिक गतिविधियों का सम्पादन करती है। 5. महोदय गुना स्थित शासकीय हवाई पट्टी पर अधोसंरचना स्थापित करने हेतु संस्था एक बडी धनराशि व्यय कर चुकी है, फलस्वरूप संस्था वर्तमान में एक बडे घाटे को वहन करते हुए तथा एक उद्देश्य एवं ध्येय को दृष्टगत रखते हुए संचालित की जा रही है, ये घाटा इसलिए वहन करना संभव हो पा रहा है क्योंकि संस्था की अन्य सहयोगी एयरकाफट मेंटीनेंश इंजीनियरिंग संस्थाएं जो की भोपाल, गुना एवं राज्य के अन्य महत्वपूर्ण शहरों में फैली हुई है, जहां से विमान अनुरक्षण अभियंता प्रशिक्षण उत्तीर्ण कर पूरे विश्व की प्रमुख एविएशन इण्डसट्रीज में अपना योगदान प्रदान कर रहें है। इसी स्तर पर संस्था गुना स्थित हवाई पट्टी से उत्तीर्ण हुए छात्रो (सीपीएल) को विकसित करने हेतु निरंतर प्रयत्नशील है, जो कि अपने देश का नाम उज्जवल कर रहें हैं एवं कई (सीपीएल) छात्र वर्तमान में प्रशिक्षणरत हैं। 6. शासन के आदेश क0–एफ–9–21/2008/पैंतालिस /भोपाल दि0– 30 जनवरी 2017 द्वारा शासन और संस्था के बीच हुए अनुबंध दि0.–10–09–2007 का नवीनीकरण नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया है, इस आदेश द्वारा संस्था के उत्साह एवं सेवा के प्रति समर्पण की भावना को अत्यंत ठेस पहुंची है। **दि0.–10–09–2007 को संस्था एवं शासन के बीच हुए अनुबंध की कंडिका–09 में हवाई पट्टी की लइसेंस अवधि के नवीनीकरण का प्रावधान प्रतिपादित किया गया है, तथा टेन्डर के साथ संलग्न प्राप्त "म0प्र0 स्थित हवाई पट्टियों पर गतिवधियां संचालित करने हेतु शर्तों" की कंडिका– 14 में भी स्पष्ट रूप से इस आशय का उल्लेख किया गया है।** अनुबंध की छायाप्रति तथा म0प्र0 स्थित हवाई पट्टियों पर गतिविधियां संचालित करने हेतु शर्तो की छायाप्रति कृपया अवलोकनार्थ संलग्न कर प्रेषित है। उपरोक्त शासनादेश अनुबंध के प्रतिकूल प्रतीत होता है, अनुबंध की कंडिका– 09 एवं शर्तो की कंडिका– 14 को दृष्टिगत रखते हुए संस्था ने गुना स्थित शासकीय हवाई पट्टी पर विशाल अधोसंरचना का विकास किया है एवं हाल ही में एयर ट्राफिक कंट्रोल, फ्यूल स्टोरेज बैरक (पेट्रोलियम मंत्रालय भारत सरकार से 10,000 ली. की क्षमता का लाइसेंस प्राप्त) तथा नाइट फ्लाइंग एक्टिविटीज व्यवस्था पर भी भारी व्यय किया है, उपरोक्त सभी कार्य शासन के सहयोग, सहायता एवं मार्गदर्शन के बिना संभव नहीं हो सकते थे जिसके लिए संस्था शासन की हृदय से आभारी है, एवं भविष्य में भी इसी प्रकार से सहयोग एवं सहायता प्रदान करने की आशा करती है जिससे वर्तमान में प्रशिक्षणरत छात्रों का भविष्य एवं मनोबल प्रभावित न हो एवं मध्यप्रदेश शासन का उद्देश्य साकार हो सके। अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि प्रस्तुत आवेदन पत्र पर, सहानुभूति पूर्वक विचार कर अनुबंध दिनांक–10/07/2007 के अनुरूप, गुना हवाई पट्टी का नवीनीकरण प्रदान कर अनुग्रहीत करेंगें संस्था इस सहयोग एवं सहायता के लिए श्रीमान जी की सदैव अभारी रहेगी। तथा दिनांक–05/05/2017 को होने वाले टेण्डर की सूची से गुना शासकीय हवाई पट्टी का नाम कृपया विलोपित कराने का कष्ट करें।	Please refer to S No. 05 of Amendment dtd 06/05/2017 to the Tender Document no F-45/Jet lease/109 Dated: 3rd Feb 2017